रविवारीय

बालेन शाह-कूटनीतिक सम्मान की सनक

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने
(अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ)

कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन का बेहतरीन माध्यम है जो किसी नियमों,परंपराओं और औपचारिकताओं का मोहताज नहीं हो सकता.नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कूटनीति को औपचारिकताओं के बाहुपाश में जकड़कर देश के दीर्घकालिक भविष्य को संकट में डाल दिया है.दरअसल बालेन शाह अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और राजनयिकों से बातचीत,वार्ताओं और संबंधों के प्रबंधन की कला के महत्व को नजरअंदाज करके खुद के देश में एक मजबूत नेता की छवि गढ़ना चाहते है.उनकी यही सनक भारत और अमेरिका जैसे सहयोगियों को नाराज कर सकती है.बालेन शाह का एक वर्ष तक किसी भी विदेशी दौरे पर न जाने का निर्णय,भारत के निमंत्रण के बावजूद विदेश यात्रा से दूरी तथा अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर से मुलाकात से इनकार ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि यह नेपाल की नई कूटनीतिक आत्मनिर्भरता का संकेत है या फिर कहीं यह कूटनीतिक सम्मान की सनक का एक नया रूप तो नहीं है.

नेपाल में लंबे समय से यह परंपरा रही है कि नया प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद सबसे पहले भारत का दौरा करता है.इसके पीछे केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भौगोलिक,सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताएं भी रही है.भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार,पारगमन मार्ग और सुरक्षा सहयोगी है.लेकिन बालेन शाह ने भारत की यात्रा को फिलहाल स्थगित करके यह संकेत देने की कोशिश की है कि नेपाल अब अपनी विदेश नीति को केवल पारंपरिक कूटनीतिक रस्मों के आधार पर नहीं चलाना चाहता.उनका मानना है कि विदेश यात्राएं केवल शिष्टाचार नहीं,बल्कि ठोस समझौतों और राष्ट्रीय हितों पर आधारित होनी चाहिए.यह निर्णय आत्मसम्मान और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक लगता है, लेकिन इसके भीतर एक दूसरा पक्ष भी दिखाई देता है.वे भारत से रिश्तों को मजबूत करने के स्थान पर ओली की भारत विरोध की राजनीति पर चलकर सीमा विवाद को तूल दे रहे है,जो उनकी राजनीतिक अदूरदर्शिता को दिखाता है.ओली ने राष्ट्रवाद की राजनीति को मजबूत करने के लिए कई बार भारत-विरोधी रुख अपनाया.2015 की सीमा नाकेबंदी के बाद उन्होंने भारत पर नेपाल को दबाव में लेने का आरोप लगाया,जिससे नेपाल में उनकी लोकप्रियता बढ़ी,लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में तनाव भी बढ़ गया.बाद में कालापानी,लिपुलेख और लिम्पियाधुरा विवाद को अत्यधिक राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करने से दोनों देशों के संबंध और जटिल हुए.नेपाल की राजनीति में भारत से दूरी दिखाना कई बार घरेलू लोकप्रियता हासिल करने का माध्यम भी रहा है.यदि बालेन शाह भारत से दूरी बनाकर केवल राष्ट्रवादी छवि को मजबूत करने की राजनीति करते है,तो इससे नेपाल की रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं.वहीं यदि वे संतुलित और व्यवहारिक कूटनीति अपनाते है,तो वे नेपाल को अधिक स्वतंत्र और स्थिर दिशा भी दे सकते है.नेपाल की अधिकांश व्यापारिक आपूर्ति,ऊर्जा,परिवहन और बाहरी संपर्क भारत के माध्यम से संचालित होते हैं.लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं और दोनों देशों के बीच खुली सीमा सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है.ऐसे में यदि नेपाल की राजनीति केवल भारत-विरोधी भावनाओं पर आधारित होने लगे,तो इसका सबसे बड़ा नुकसान स्वयं नेपाल को ही उठाना पड़ सकता है.नेपाल की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास केवल प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद या भारत से दूरी बनाकर संभव नहीं है.नेपाल की भौगोलिक,आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकता ऐसी है कि भारत के साथ मजबूत और व्यवहारिक संबंध उसके राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं.

नेपाल की आर्थिक,सामाजिक और भौगोलिक संरचना भारत से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि भारत को नजरअंदाज करके नेपाल दीर्घकालिक स्थिरता और विकास की कल्पना नही कर सकता.इन सबके बीच प्रधानमंत्री बालेन शाह को यह भी समझना होगा की कूटनीति में सम्मान महत्वपूर्ण होता है,परंतु अत्यधिक प्रतीकात्मकता कभी-कभी व्यवहारिक राजनीति को कमजोर कर देती है.अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल प्रोटोकॉल से नहीं चलते,वे संवाद,संपर्क और लचीलेपन पर भी आधारित होते हैं.यदि कोई नेतृत्व यह तय कर ले कि वह केवल राष्ट्राध्यक्षों या विदेश मंत्रियों के स्तर के लोगों से ही मिलेगा,तो यह व्यावहारिक कूटनीति की जगह प्रतिष्ठा-आधारित राजनीति को बढ़ावा दे सकता है.

यही स्थिति अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर के मामले में देखने को मिली.अमेरिकी पक्ष ने काठमांडू यात्रा के दौरान बालेन शाह से मुलाकात का अनुरोध किया,लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि प्रधानमंत्री घरेलू विकास और सुशासन के कार्यों में व्यस्त है.यह माना जा रहा है की बालेन शाह ने यह कड़ा प्रोटोकॉल बनाया है कि वे केवल समकक्ष या उससे उच्च स्तर के नेताओं से ही मिलेंगे.यह निर्णय नेपाल की गरिमामय कूटनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया,लेकिन वास्तव में इसमें कूटनीतिक अकुशलता भी दिखाई दी.

अमेरिकी दूत सर्जियो गोर कोई साधारण राजनयिक नहीं है.वे राष्ट्रपति ट्रम्प के अत्यंत करीबी सहयोगियों में माने जाते है तथा उनका प्रभाव अमेरिकी सत्ता संरचना के भीतर गहरा माना जाता है.दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में उनकी भूमिका केवल औपचारिक नहीं,बल्कि रणनीतिक है.वे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मध्य एशिया से जुड़ी अमेरिकी नीति के महत्वपूर्ण चेहरों में गिने जाते हैं.ऐसे व्यक्ति से मुलाकात को केवल प्रोटोकॉल के आधार पर टालना कई कूटनीतिक हलकों में अपरिपक्वता के रूप में देखा जाना चाहिए.यह संवादहीनता नेपाल के राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदायक हो सकती है.

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अक्सर विभिन्न देशों के शीर्ष अधिकारियों से मिलते हैं, जिसमें पुतिन जैसे शीर्ष राजनीतिज्ञ भी शामिल है.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी परिस्थिति और रणनीतिक जरूरत के अनुसार अलग अलग स्तर के राजनयिकों से संवाद करते है. आधुनिक कूटनीति में लचीलापन शक्ति का प्रतीक माना जाता है,कमजोरी का नहीं.नेपाल की स्थिति और भी संवेदनशील है,यह भारत और चीन के बीच स्थित एक छोटा लेकिन रणनीतिक राष्ट्र है.अमेरिका लंबे समय से नेपाल में विकास,लोकतंत्र और अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश करता रहा है.अभी नेपाल के आर्थिक हालात बेहतर नहीं है, बालेन शाह,सर्जियो गोर से मिलकर कई अहम समझौतों की ओर कदम बढ़ा सकते थे,लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री ने यह अवसर गंवा दिया.

शाह की लोकप्रियता मुख्यत: उनकी परंपरागत सत्ता ढांचे की विरोधी छवि और स्थानीय प्रशासनिक सुधारों से बनी है.वे पारंपरिक राजनीतिक वर्ग से अलग दिखना चाहते हैं.संभवत: यही कारण है कि वे विदेश नीति में भी एक नई शैली प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं.लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति घरेलू राजनीति से अलग होती है. यहां केवल लोकप्रियता नही,बल्कि निरंतर संवाद, रणनीतिक धैर्य और व्यावहारिकता भी जरूरी होती है.

> बालेन शाह को नेपाल की जनता ने पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था से अलग एक विकल्प के रूप में उभरते हुए देखा.उन्हें सत्ता इसलिए सौंपी गई कि वे देश के प्रशासनिक ढांचे को बेहतर करे,भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को कम करें तथा नेपाल को अधिक मजबूत,आत्मनिर्भर और व्यवस्थित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करें.भू-राजनीतिक रूप से नेपाल एक संवेदनशील देश है और उसके लिए कूटनीति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है.भारत,चीन और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के बीच स्थित नेपाल को अत्यधिक संतुलित और व्यवहारिक कूटनीति की आवश्यकता होती है.किसी प्रभावशाली प्रतिनिधि या रणनीतिक शक्ति से दूरी बनाना कई बार अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है. नेपाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार और विकास बाहरी सहयोग से जुड़ा हुआ है,यहां कूटनीतिक कठोरता जोखिम पैदा कर सकती है.बालेन शाह के पास नेपाल की राजनीति को नई दिशा देने का अवसर है.यदि वे घरेलू सुधारों के साथ-साथ व्यवहारिक और परिपक्व कूटनीति अपनाते है,तो वे नेपाल को क्षेत्रीय राजनीति में अधिक सम्मानजनक और स्थिर स्थिति दिला सकते है.लेकिन यदि विदेश नीति केवल व्यक्तिगत छवि निर्माण तक सीमित रह गई,तो इससे नेपाल की आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती है.

व्यंग्य

हाय हाय मिर्ची उफ... उफ मिर्ची...

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

अप्रैल माह से मिर्ची की झाल देश भर में सिर चढ़ कर बोल रही है.इसकी झाल आज तक पश्चिम बंगाल में विपक्ष की जुबान पर झाल की, सी.. सी..सी आज भी बरकरार है.मोदी जी भी,भई गज़ब ही हैं.चुनाव प्रचार के दौरान वह झारग्राम पहुंच गए.उन्होंने वहां दस रुपैए में वो रंग जमाया कि क्या कहने. उन्होंने वहां बता दिया कि दस रूपट्टी में वो किया जा सकता है जो 15 साल को चुन मुन कांग्रेस सरकार को चलता कर दे. कुछ तो स्पेशल है इस बंदे में.तभी तो मोदी ने राष्ट्र गीत वन्देमातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन जैसा कानूनी दर्जा दे डाला.

मोदी जी ने झारग्राम में दस रुपैए में बंगाल की प्रसिद्ध झालमुड़ी खरीद कर खुद तो खाई ही खाई साथ ही वहां आसपास खड़ी महिलाओं और बच्चों को भी उसी दस रुपैए से लंगर भी चखा डाला.ये गुजराती भी गज़ब होते हैं.कम पैसों में वो कैसा रंग जमा देते हैं यह मोदी जी ने झारग्राम में दिखा दिया.कहा ये जाता है कि गुजराती इतने प्रोफेशनल होते हैं कि रेत में से भी तेल निकालने का कौशल और हौसला रखते हैं.

झारग्राम में मोदी ने वहां की झारमुड़ी खरीद कर फक्का क्या मारा,लोगों के मुंह अपने आप ऐसे खुल गए जैसे वो खुद फक्का लगा रहे हों.भैया सच्ची बात तो यह है कि इसके पहले तो हमने झारमुड़ी का नाम तक नहीं सुना था.हां, यदि इससे मिलता जुलता कोई नाम सुना था तो वह था मालगुड़ी .अरे !वही मालगुड़ी जो टीवी के ब्लैक व्हाइट के जमाने में दूरदर्शन पर आने वाला सीरियल था मालगुड़ी डेज नहीं याद आया?

अरे वह भोला भाला धोती कमीज और काली टोपी लगाए, शरारती सा लड़का, अपना स्वामी.सीरियल का वह मधुर संगीत ताना न न ना.ताना न न ना. अब याद आया ना.यह सीरियल और इसका संगीत खूब मशहूर हो गया था. तो भाइयों हमने मालगुड़ी का नाम ही सुन रखा था.मोदी जी ने पहली बार दस रूपट्टी अपने जेब से निकाल कर.झालमुड़ी को अमर कर डाला. मोदी जी का अपनी जेब से दस रुपए का नोट निकाल कर गजब ही कर डाला.वाह ! क्या जादू है.नेताओं के बारे में यह मशहूर है कि वह अपनी जेब में न तो पैसे रखते हैं और न ही अपनी जेब से पैसे निकालते हैं.वो तो जनता की जेब से पैसा निकालने के लिए मशहूर होते हैं.

पर मोदी जी ने एक दम नया कड़क दस का नोट निकाल कर भौंचक कर दिया.हमारे पास तो मैले कुचैले ऐसे नोट आते हैं कि लगता है शर्ट की पॉकेट ही गंदी न हो जाए.पीएम के पास नया नोट और हमारे पास मैला कुचैला.यह तो रंग भेद है.देख रहे हो जज साहब.जनता के साथ कितनी ज्यादती हो रही है ? बरहाल मोदी जी ने एक ही झटके में झारग्राम की झालमुडी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया.

आप का सवाल होगा कि झालमुड़ी में खास क्या है ? तो भाइयों झालमुड़ी में यदि कुछ खास है तो वह है झाल.इसमें झाल ही खास है.इसमें कोई झोल नहीं है कि झालमुड़ी में झाल ही खास है.पहेलियां न बुझाते हुए आइए अब बता ही देते हैं कि झाल का मतलब क्या है.झाल का मतलब है तीखापन, चटपटा पन.खड़ी बोली में बोलें तो मिर्ची.मोदी जी ने मिर्ची वाली झालमुड़ी का जो चटखारा मारा तो मिर्च की झाल दीदी की भवानीपुर तक जा पहुंची.उनके मुंह से सी..सी की आवाज निकलने लगीं.भारत के विभिन्न भागों में झालमुड़ी जैसी जो डिश मिलती है उसको भेल भी कहा जाता है.इसमें मुरमुरे, मिर्च, सरसों का तेल, प्याज, हरा धनिया,नींबू, कच्ची केरी के स्लाइस शामिल होता है.इसकी तुलना विभिन्न पार्टियों द्वारा तैयार किए जाने वाले गठबंधनों यानी एलायंस से की जा सकती है.इसे भानुमति का कुनबा भी कहा जा सकता है.कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा।

अरे वही मिर्ची जो गोविंदा के रस्ते पर जाते समय - भेलपुरी खाते समय लोगों को लगी थी.तभी तो गोविंदा ने कहा तुम को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं.मिर्ची की ख्याति इतनी और ऐसी है कि व्याकरण शास्त्री भी उसे कहावत में शामिल करने को मजबूर हो गए.उनको भी मिर्ची अच्छी लगी.मिर्ची लगना देश में आम बोलचाल की भाषा बन गई.टाइम्स ग्रुप ने रेडियो मिर्ची नाम का एंटरटेंट रेडियो चैनल ही खोल डाला. मिर्ची से अब हम वापस झालमुड़ी पर लौटते हैं.तो भाइयों गहरे शोध और अनुसंधान से यह पता किया गया कि आखिर मोदी जी को झालमुड़ी क्यों पसंद आई.उन्होंने इसे खाने का क्यों डिसाइड किया ? तो इसका करण था इसमें डलने वाले आधा दर्जन से ज्यादा इंग्रीडिएंट.मोदी जी को शायद झालमुड़ी में जो विभिन्न तरह की डाली जाने वाली सामग्रियां का मेल सियासी दलों के एलायंस या गठबंधन जैसा लगा हो उन्होंने सोचा हो चलो पहले इसे निबटा देते हैं.जब 4 मई को रिजल्ट आए तो सब नक्शा ही बदल गया.सब झालामुड़ी खा रहे थे.एक बात और गूगल पर झालमुड़ी शब्द पिछले 22 सालों में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द बन गया.

बंगाल जीत के बाद भाजपा की अगली राजनीति

श्याम यादव
राजनीतिक लेखक

भारतीय जनता पार्टी के खाते में पश्चिम बंगाल की जीत आने के बाद देश की राजनीति का माहौल तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है. यह सिर्फ एक राज्य का चुनाव परिणाम नहीं है. इसके राजनीतिक संदेश दूर तक जाएंगे. अब साफ दिखने लगा है कि भाजपा केवल अपनी पुरानी जमीन बचाने की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि लगातार नया भूगोल जोड़ने में लगी है. दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी अपनी बची हुई जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है. पश्चिम बंगाल लंबे समय तक ऐसा राज्य रहा जहाँ भाजपा को बाहरी पार्टी माना जाता था. पहले वामपंथ और बाद में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ राजनीति को अपने तरीके से चलाया. भाजपा कई चुनाव लड़ती रही, लेकिन सत्ता तक पहुँच नहीं पाई. इसलिए बंगाल की इस जीत को भाजपा साधारण घटना की तरह नहीं देख रही. पार्टी इसे अपनी वैचारिक और राजनीतिक दोनों तरह की बड़ी उपलब्धि बताकर पेश कर रही है.

अब देश के लगभग बाइस राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकारें हैं. कई राज्यों में क्षेत्रीय दल जरूर अपने-अपने प्रभाव के सहारे टिके हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की बढ़ती ताकत साफ दिखाई दे रही है. यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को अब सिर्फ राज्य स्तर की लड़ाई नहीं माना जा रहा. आने वाले वर्षों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम होगा. दिल्ली की सत्ता का रास्ता आज भी लखनऊ से होकर गुजरता है. विपक्ष चाहे जितनी बैठकें कर ले, लेकिन फिलहाल ऐसा माहौल नहीं दिखता कि भाजपा को सीधी चुनौती मिल रही हो. बिहार और बंगाल के चुनावों के बाद विपक्षी गठबंधन को लेकर जो उत्साह दिखा था, वह अब ठंडा पड़ चुका है.

भाजपा की ताकत सिर्फ उसका प्रचार नहीं है. उसकी असली ताकत यह है कि पार्टी और उससे जुड़े संगठन लगातार मैदान में सक्रिय रहते हैं. चुनाव खत्म होने के बाद भी भाजपा अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है. बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ता, योजनाओं का सीधा लाभ लेने वाला वर्ग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भाजपा को बढ़त दिलाती है. यही वजह है कि कई जगह सरकार के खिलाफ नाराजगी होने के बाद भी भाजपा मुकाबले में कमजोर नहीं पड़ती.

बंगाल की जीत भाजपा को सिर्फ एक और राज्य नहीं देगी, बल्कि पार्टी के भीतर यह विश्वास भी मजबूत करेगी कि अब वह देश के किसी भी हिस्से में सत्ता तक पहुँच सकती है. यही कारण है कि आने वाले समय में भाजपा और ज्यादा आक्रामक राजनीतिक विस्तार की रणनीति पर चल सकती है. दक्षिण भारत से लेकर पंजाब तक, पार्टी उन राज्यों पर ध्यान बढ़ाएगी जहाँ अभी उसकी पकड़ पूरी तरह मजबूत नहीं है.

इसके साथ-साथ पंजाब की राजनीति पर भी नजर रहेगी. पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने वहाँ नई चर्चाएँ शुरू कर दी हैं. राज्यसभा सांसदों के भाजपा के करीब जाने की खबरों के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले समय में पंजाब सरकार पर दबाव बढ़ सकता है. हालाँकि केवल राज्यसभा सांसदों के जाने से सरकार नहीं गिरती, क्योंकि सरकार विधानसभा के बहुमत से चलती है. लेकिन राजनीति में संकेत हमेशा सीधे नहीं होते. कई बार छोटे घटनाक्रम आगे चलकर बड़े बदलाव की भूमिका बन जाते हैं. भाजपा यदि पंजाब में अपना संगठन बढ़ाने और विपक्षी दलों में सेंध लगाने की रणनीति पर चलती है, तो आने वाले समय में वहाँ की राजनीति और दिलचस्प हो सकती है.

हालाँकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता. जनता कब किसे ऊपर उठाए और किसे नीचे ले आए, इसका अंदाजा बड़े-बड़े दल नहीं लगा पाते. लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली हर पार्टी को एक समय बाद नाराजगी, थकान और स्थानीय असंतोष का सामना करना पड़ता है. भाजपा के सामने भी आगे यही चुनौती होगी.

'बहुमत का मतलब 118 नहीं होता है, महामहिम जी!

राजीव खण्डेलवाल
(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल सुधार न्यास)

तमिलनाडु की राजनीति दशकों तक द्रविड़ दलों की 'दो ध्रुवीय रेल पटरी' पर चलती रही. 1944 में ई. वी. रामासामी पेरियार द्वारा स्थापित 'द्रविड़ कड़गम') से निकली डीएमके और बाद में उससे अलग होकर बनी एआईएडीएमके ने लगभग छह दशकों तक तमिल तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व को अपनी मुट्ठी में बनाए रखा. तथापि दूसरी ओर डीएमके और एडीआईएमके के संभावित 'साझा सत्ता समीकरण' की अफवाहों की चर्चाओं को जन्म देकर द्रविड़ की संयुक्त उपक्रम राजनीति के नए कोण की ओर इशारा करने का प्रयास किया जा रहा है. सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार और 'थलापति' के नाम से लोकप्रिय जोसेफ विजय चंद्रशेखर की नवगठित पार्टी 'टीवीके' ने केवल दो वर्षों 2 माह में तमिल राजनीति की जमी-जमाई बिसात उलट कर रख दी. यह परिणाम द्रविड़ राजनीति के 'एकाधिकार' के विरुद्ध जनता का मत माना जा सकता है. 'चुनाव परिणाम : सत्ता के समीकरण उलट गए.' तमिलनाडु विधानसभा के परिणाम निम्नानुसार रहे— टीवीके : 108 प्रभावशाली 107., डीएमके गठबंधन : 73, एआईएडीएमके गठबंधन : 53

इस चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा राजनीतिक विस्फोट यह रहा कि पहली बार चुनाव लड़ रही नवगठित टीवीके ने लगभग 34.92% मत प्राप्त कर लिए. यह प्रतिशत 1977 में एम. जी. रामचंद्रन द्वारा स्थापित एआईएडीएमके को उसके प्रथम चुनाव में मिले मत प्रतिशत से भी अधिक है. हालांकि सीटें अपेक्षाकृत कम रहीं, परंतु राजनीति में कहा जाता है — 'बीज छोटा हो सकता है, लेकिन वटवृक्ष बनने की क्षमता उसी में होती है.'

बहुमत का वास्तविक अर्थ क्या है?- यहीं से संवैधानिक और राजनीतिक विवाद प्रारंभ होता है. राज्यपाल द्वारा विजय से 118 विधायकों के समर्थन पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में 'बहुमत' का अर्थ सदन की कुल संख्या का आधा + एक ही होता है संविधान, न्यायालय और संसदीय परंपराएँ इस प्रश्न का उत्तर कहीं अधिक गहराई से देती हैं. 'सरकारिया आयोग'83-88, 'पुंछी आयोग' तथा उच्चतम न्यायालय के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय — जैसे : एस. आर. बोम्मई 1994,, जगदंबिका पाल 1998, रामेश्वर प्रसाद 2006, नाबाम रेबिया 2016, शिवराज सिंह चौहान 2020

इन सभी में एक मूल सिद्धांत स्थापित किया गया है कि — 'बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं, विधानसभा के फ्लोर पर होगा.' अनुच्छेद 154 (सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करना) और उसी से जुड़ा अनुच्छेद 256 (राष्ट्रपति शासन की सिफारिश) के अधीन राज्यपाल के पास सामान्यत: निम्न क्रमानुसार विकल्प होते हैं— स्पष्ट बहुमत वाली पार्टी को, अथवा चुनाव-पूर्व गठबंधन को आमंत्रित करना. त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में चुनाव-पश्चात गठबंधन को अवसर देना. यदि कोई गठबंधन न हो तो सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने हेतु इस शर्त के साथ बुलाना कि नियत समय में विश्वासमत सिद्ध करने को कहना. यदि कोई स्थायी सरकार संभव न हो तो अंतिम विकल्प के रूप में विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने की सरकार बनने की संभावना को तलाश में के लिए कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना.

राज्यपाल का विवेकाधिकार एवं संतुष्टि. 'राजनीतिक पसंद' नहीं हो सकता. वह 'संवैधानिक संतुष्टि' होना चाहिए, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है. प्रथम दृष्टया राज्यपाल का यह तर्क सही लग सकता है कि 118 का समर्थन न होने से विजय को आमंत्रित नहीं किया जाए. लेकिन संवैधानिक कानूनी तथ्यात्मक, परंपरा और नैतिक वास्तविकता इससे अलग है. सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का अर्थ यह नहीं कि सदन की कुल संख्या का बहुमत हर परिस्थिति में हो. बल्कि विश्वासमत के दिन उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत ही आवश्यक है. यही संसदीय लोकतंत्र की मूल आत्मा है. यदि विपक्ष मतदान से दूर रहे, अनुपस्थित रहे या तटस्थ रहे, तो अल्पमत सरकार भी बहुमत सिद्ध कर सकती है. भारतीय राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है. राजनीति में अक्सर कहा जाता है — 'सत्ता गणित से नहीं, समय और रणनीति से चलती है.'

क्या विजय के पास बहुमत की संभावना है?- वर्तमान परिस्थितियों में विजय की दावेदारी कई कारणों से मजबूत दिखाई देती है— सबसे बड़ी पार्टी टीवीके है. सरकार बनाने का दावा केवल विजय ने प्रस्तुत किया है. किसी अन्य गठबंधन ने अभी तक औपचारिक दावा नहीं किया. किसी दल ने राज्यपाल के समक्ष विजय के दावे का प्रत्यक्ष विरोध भी नहीं किया.

एग्री स्टैक : भारत की डिजिटल कृषि क्रांति

डॉ. देवेश चतुर्वेदी

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है. इस क्षेत्र में कुल श्रमशक्ति का लगभग 46प्रतिशत हिस्सा जुटा हुआ है.पिछले दशक में सरकार की ओर सेउत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने, फसलों के विविधीकरण, खेती की लागत में कमी लाने, कृषि उत्पादों की बेहतर कीमत अर्जित करने, जलवायु के अनुकूल ढालने और जोखिमों को कम करने की बहुआयामी रणनीति के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के ठोस प्रयास किए गए हैं. केन्द्र प्रायोजित या केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के जरिए किसानों को विभिन्न सेवाओं या लाभों की निर्बाध, पारदर्शी और कुशल आपूर्तिसंघीय या राज्य स्तर की सरकार की प्राथमिकता है.कुल कृषि भूमि का स्वामित्व और उस भूमि पर बोई गई फसलों का इतिहास किसी भी योजना के लाभ के लिए किसी भी किसान (चाहे वह मालिक हो, पट्टेदार हो या फिर बटाईदार हो) की पात्रता के आकलन कीजरूरी शर्त है.हालांकि, देश भर में भूमि से संबंधित प्रशासन में पायी जाने वाली व्यापक भिन्नताएं एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं. स्वामित्व और बुवाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को संकलित करने वाले एक मानकीकृत किसान डेटाबेस के महत्व एवंजरूरत को पहचानते हुए, सरकार ने वर्ष 2024 में डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की.किसानों के इस डेटाबेस कोमजबूत सहमति तंत्र के साथ गतिशील रूप से अद्यतन किया जाता है. एग्री स्टैक,इस डिजिटल कृषि मिशन का एक प्रमुख स्तंभ है.यह अब इस मिशन के एक मौन लेकिन सशक्त परिवर्तनकारी स्तंभ के रूप में उभर रहा है.इसमें तीन विवरणी (रजिस्ट्री)-खेत, किसान और बोई गई फसल - शामिल हैं.एग्री स्टैक भारत की कृषि से जुड़ी यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआतका इशारा करता है. एक ऐसा अध्याय, जो माननीय प्रधानमंत्री के 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लक्ष्यके साथ गहराई से जुड़ा हुआ है. खेतवाली रजिस्ट्री में भौगोलिक संदर्भों के आधार पर कृषि भूखंडों का डेटाबेस शामिल होता है.इनमें से प्रत्येक भूखंड को एक अनूठी कृषि आईडी प्रदान की जाती है.दूसरीपरत में, प्रत्येक भूमि के मालिक किसान को एक अनूठी फार्म आईडी प्रदान की जा रही है.इस आईडी में स्वामित्व वाली प्रत्येक भूखंड से संबंधित जरूरीजानकारियों के साथ-साथ सह-स्वामित्व के मामले में हिस्सेदारी का उल्लेखभी शामिल है.यह डेटा अधिकार अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स)से गतिशील रूप से जुड़ा हुआ है ताकि विरासत, बिक्री आदि के कारण स्वामित्व में हुआ कोई भी बदलाव किसान रजिस्ट्री में अद्यतन हो जाए.तीसरी परत में प्रत्येक भूखंड पर बोई गई फसल का विवरण शामिल होता है.यह विवरण बुवाई पूरी होने के बाद प्रत्येक फसल के मौसम में किए गए डिजिटल/तकनीक आधारित फसल सर्वेक्षण के जरिए हासिल किया जाता है. केन्द्र सरकार ने विभिन्न समझौता ज्ञापनों के जरिए 35 राज्यों और केन्द्र- शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी की है.इस डिजिटल मिशन को केन्द्र और राज्य के बीच मजबूत सहयोग के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है.इसमें पूर्ण समावेशन सुनिश्चित करते हुए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. एग्री स्टैक एक संघीय डेटाबेस है जिसका स्वामित्व राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के पास है, लेकिन केन्द्र सरकार सेवाओं की आपूर्ति और डेटा विश्लेषण के लिए इसका उपयोग कर सकती है.इसका उद्देश्य प्रत्येक किसान के लिए एक सत्यापित डिजिटल पहचान बनाना, उस पहचान को सटीक रूप से मैप किए गएभूखंड से जोड़ना और प्रत्येक मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को दर्जकरना है.यह स्टैक नियमों पर आधारित एवं स्वचालित सेवा वितरण को विभिन्न योजनाओं और भौगोलिक क्षेत्रों में संभव बनाता है.

(लेखक भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं)

डिजिटल फसल सर्वेक्षण : फसल की वास्तविक जानकारी

वर्ष 2025-26 में, 24 राज्यों ने 600 से अधिक ज़िलों में लगभग 30 करोड़ भूखंडों पर मोबाइल उपकरणों, जियोटैगिंग और सैटेलाइट की मदद से डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया. यह सर्वेक्षण पारंपरिक विधियों से हटकर एक महत्वपूर्ण बदलाव है. पारंपरिक विधियांअक्सर धीमी होती थीं और उनमें विसंगतियों या त्रुटियों की गुंजाइश अधिक रहती थी. यह डेटा उपज का अनुमान लगाने, खरीदकी योजना बनाने और बाजार से संबंधित पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है.यह सूखे, बाढ़ या कीटों के कारण फसल पर पड़ने वाले दबाव की शीघ्र पहचान करके आपदा की तैयारी को भी ठोस बनाता है. किसानों के लिए, बेहतर डेटा समय पर एवं फसल-विशेष से जुड़ी सलाहऔर गड़बड़ होने पर त्वरित सहायता प्रदान करता है.